आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरूवार 22.01.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया।
- आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों के सेंडई फ्रेमवर्क के तहत वर्ष 2015 से 2030 तक के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- राज्य में समान नागरिक संहिता के पंजीकरण अब अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश्ज्ञं

अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पावन कुंभ क्षेत्र है, जिसे सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस दिव्य धरा पर संतों ने अपने आत्मबल से स्वयं के साथ–साथ करोड़ों लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है।

श्री शाह ने कहा कि इसी भूमि पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का महान कार्य किया। उन्होंने अखंड ज्योति सम्मेलन को आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने व्यक्ति निर्माण के माध्यम से आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

प्रगति समीक्षा

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने राज्य के विभिन्न विभागों के सेंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित बैठक में उन्होंने सेंडई फ्रेमवर्क में वर्ष 2015 से 2030 तक के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने विभाग का कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।

सेंडई फ्रेमवर्क आपदाओं से होने वाली जनहानि, प्रभावित लोगों की संख्या, आर्थिक क्षति व बुनियादी सेवाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करता है। श्री सुमन ने कहा कि सेंडई फ्रेमवर्क की पहली प्राथमिकता आपदा जोखिम को समझना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण एवं उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

दूसरी प्राथमिकता आपदा जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। इसके लिए तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। जबकि तीसरी प्राथमिकता आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश के संबंध में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम कम करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा चौथी प्राथमिकता आपदा के प्रति तैयारी तथा प्रभावी प्रतिक्रिया एवं पुनर्निर्माण पर जोर देना है।

डिजिटाइजेशन

प्रदेश में सहकारिता व्यवस्था के डिजिटलीकरण के तहत अब तक 405 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ई–पैक्स में बदला जा चुका है। शेष समितियों का डिजिटलीकरण जारी है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी है।

सहकारिता मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ई–पैक्स के माध्यम से गांवों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी और समितियां मल्टीपर्पज सेंटर के रूप में कार्य करेंगी। डिजिटलीकरण से लेन–देन ऑनलाइन होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं और महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

डॉक्टर रावत ने बताया कि शेष समितियों के कम्प्यूटरीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और ई–पैक्स का ई–ऑडिट भी किया जा रहा है।

यूसीसी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के पंजीकरण को अब बहुभाषी बनाया गया है। यूसीसी से संबंधित सेवाएं अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। आवेदक अपनी पसंदीदा भाषा में नियम, प्रक्रियाएं और आवश्यक दस्तावेज समझकर आवेदन कर सकते हैं।

यूसीसी पोर्टल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता–एआई आधारित सहायता की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे नागरिक स्वयं ऑनलाइन और फेसलेस पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद, वसीयत, लिव–इन पंजीकरण और लिव–इन संबंध समाप्त करने जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

गौरतलब है कि पिछले एक साल में इस प्रक्रिया के माध्यम से पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और कोई निजता उल्लंघन या शिकायत दर्ज नहीं हुई। आवेदन पर औसतन पांच दिनों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिससे नागरिकों का समय भी बच रहा है।

बैठक

मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित ज़िलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित बारिश, बर्फबारी, पाला और शीतलहर से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जनपदों की तैयारियों की समीक्षा की गई और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट–

इस बीच, ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों और जरूरतमंद क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था करने तथा रैनबसेरों में बिजली, पेयजल, बिस्तर और हीटर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को देने और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है।

जांच

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से ट्रांसफर हुए शस्त्र लाइसेंसों की जांच के लिए एसटीएफ ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले के बाद दूसरे जिलों में भी बाहरी राज्यों से आए लाइसेंसों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद ट्रांसफर हुए सभी लाइसेंसों की सूची तलब की गई है और प्रत्येक लाइसेंस की गहन जांच की जाएगी। अवैध या फर्जी पाए जाने पर संबंधित शस्त्र धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देहरादून में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में कुल 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।